



उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सूभाष रोड, देहरादून

E-mail : infodirector.uk@gmail.com

Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 07 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-06(07 / 50)

मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है।

शनिवार को अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने शहर में किये जा रहे अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, सीलिंग व सीमांकन के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने रायपुर रोड स्थित डील फ़ैक्ट्री, नाला पानी चौक व हरिद्वार रोड स्थित रोडवेज वर्कशॉप के आस-पास किये जा रहे अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, सीमांकन व सीलिंग की कार्यवाही का निरीक्षण किया। इस अभियान के अन्तर्गत शनिवार को 144 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 271 अतिक्रमणों के चिन्हिकरण का कार्य किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 795 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 2425 अतिक्रमणों के चिन्हिकरण व 75 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हिकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव को निर्देश दिये कि जिन अवैध भवनों को अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, ऐसे भवन स्वामियों से भवन के ध्वस्तीकरण किये जाने का चालान काटने के बाद पैसा वसूली की कार्यवाही में तेजी लाई जाए। चालान काटने व पैसा वसूली के कार्य में ढिलाई बर्दास्त नहीं की जायेगी। जो लोग दुबारा अतिक्रमण करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध आई.पी.सी. की धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज की जाए। ध्वस्तीकरण के कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिये कि अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान जिन-जिन स्थानों से बड़े व छोटे होर्डिंग्स को ध्वस्त किया गया है। ऐसे स्थानों पर पुनः होर्डिंग्स न लगने पाए, इसकी पूर्ण निगरानी रखी जाए।

श्री ओमप्रकाश ने जिलाधिकारी देहरादून व पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिये कि देहरादून में लगने वाले संडे मार्केट को किसी भी दशा में न लगने दिया जाए, जिससे की संडे मार्केट लगने वाले स्थान के आस-पास यातायात का दबाव कम रहे व टास्क फोर्स द्वारा अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुगमता से सम्पादित की जा सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति संडे मार्केट लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव, जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरुगेशन, मुख्य नगर आयुक्त श्री विजय कुमार जोगदंडे, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुड़े संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड की प्रसिद्ध लोकगायिका श्रीमती कबूतरी देवी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के लोक संगीत को बढ़ावा देने में स्व. कबूतरी देवी का योगदान अतुलनीय रहा है। उत्तराखण्ड के ऋतु आधारित गीतों की वे विशेषज्ञ गायिका थी :- **पहाड़ों को ठंडो पाणी, कि भलि मीठी वाणी.....** गीत आज भी आम उत्तराखण्ड के जेहन से जुड़ा है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कबूतरी देवी ने पिथौरागढ़ के सुदूर ग्रामीण अंचल से निकलकर उत्तराखण्ड की पहाड़ी संस्कृति और लोकगीत शैली को अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर नई पहचान दिलाई। उनका जाना पर्वतीय लोक संगीत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कबूतरी देवी जैसे लोक संस्कृति के वाहक का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा तथा वे हर उत्तराखण्ड के दिल में जीवित रहेंगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्व. कबूतरी देवी हमारे पर्वतीय लोक संगीत एवं लोक संस्कृति की जीवंत प्रतिमूर्ति थी। उनके गीतों में शास्त्रीय संगीत का पुट भी मौजूद था। सत्तर के दशक से आकाशवाणी के उत्तरायणी कार्यक्रम से जुड़ी रहकर अपनी लोक संस्कृति एवं लोक संगीत से देश व दुनिया को रूबरू कराती रही।

ज्ञातव्य है कि उत्तराखण्ड की तीजनबाई कही जाने वाली कबूतरी देवी ने पहली बार दादी-नानी के लोकगीतों को आकाशवाणी और प्रतिष्ठित मंचो के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया था। जब उन्होंने आकाशवाणी पर प्रस्तुतियां देनी शुरू की थीं, उस वक्त कोई महिला संस्कृतिकर्मी आकाशवाणी के लिए नहीं गाती थीं। 70 के दशक में उन्होंने पहली बार पहाड़ के गांव से स्टूडियो पहुंचकर रेडियो जगत में अपने गीतों से धूम मचा दी थी। कबूतरी देवी ने आकाशवाणी के लिए करीब 100 से अधिक गीत गाए। उनके गीत आकाशवाणी के रामपुर, लखनऊ, नजीबाबाद और चर्चगेट, मुंबई के केन्द्रों से प्रसारित होते थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को ले. जनरल चैरिश मैथसन, पीवीएसएम, एसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण पश्चिम कमान, कर्नल ऑफ द गढ़वाल राईफल्स एवं गढ़वाल स्काउट्स ने शिष्टाचार भेंट की।

ले. जनरल चैरिश मैथसन ने मुख्यमंत्री से गढ़वाल रेजीमेंट के मुख्यालय लैंसडाउन में पेयजल की समस्या के निदान के लिए भैरवगढ़ी जल परियोजना के संबंध में वार्ता की। उन्होंने इस पेयजल योजना के समाधान का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि लैंसडाउन की पेयजल समस्या के समाधान के लिए 64 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। जिसमें सेना द्वारा 23 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जानी है। जिसमें से अभी तक 09 करोड़ रुपये प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध कराई जा चुकी है। ले. जनरल चैरिश मैथसन ने कहा कि शेष 14 करोड़ की धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराई जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सचिव पेयजल को दिसम्बर तक इस पेयजल योजना को पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि लैंसडाउन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान होना जरूरी है। इसके लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

राज्य में पर्याप्त संख्या में ड्रग्स इन्सपेक्टरों की जल्द से जल्द व्यवस्था-मुख्यमंत्री

- सेलाकुई चौकी को थाने में तब्दील किया जाएगा तथा यहां पर महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी
- फार्मा उद्योग की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु फार्मा उद्यमियों तथा बायो डायवर्सिटी बोर्ड की एक बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी

राज्य में नशे के बढ़ते प्रचलन पर कड़ाई से नियन्त्रण हेतु पर्याप्त संख्या में ड्रग्स इन्सपेक्टरों की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाएगी। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेलाकुई चौकी को थाने में तब्दील किया जाएगा तथा यहां पर महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फार्मा उद्योग की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु फार्मा उद्यमियों तथा बायो डायवर्सिटी बोर्ड की एक बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी। राज्य में फार्मा उद्योग को उत्तर पूर्वी राज्यों के समान आयकर में छूट हेतु एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। फार्मा इकाईयों को परिवहन अनुदान (ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी) देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में राज्य में फार्मा उद्योग की प्रगति की समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने युवाओं में नशे के बढ़ते प्रचलन पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि जल्द से जल्द दवाईयों की जांच व नशे के व्यापार करने वालों पर कड़े नियन्त्रण हेतु पर्याप्त संख्या में ड्रग्स इन्सपेक्टरों की व्यवस्था की जाए। बैठक के दौरान सचिव स्वास्थ्य ने जानकारी दी कि राज्य की स्थापना के समय मात्र 1500 मेडिकल स्टोर थे जिनकी वर्तमान में संख्या 15000 तक पहुंच गई है। राज्य में 80 ड्रग्स इन्सपेक्टरों की आवश्यकता है जबकि वर्तमान में मात्र 4 ड्रग्स इन्सपेक्टर कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य की दुर्गम पहाड़ी स्थिती को ध्यान में रखते हुए फार्मा उद्योग हेतु मशीनरी, कच्चा माल एवं पैकिंग के कारण दवाईयों की लागत बढ़ने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फार्मा इकाईयों को माल भाड़े में अनुदान के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सचिव ऊर्जा तथा ऊर्जा निगमों के अधिकारियों को फार्मा उद्योगों को अबाधित बिजली आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने हरिद्वार में एक्सपोर्ट हब स्थापित करने की संभावनाओं पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि निर्यात की जाने वाली दवाईया अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों (भ्यू च्बै र्थ्वा ए डम्त्।) पर खरी उतरे इसके लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाए स्थापित करने हेतु प्रस्ताव पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फार्मा उद्योग तथा बायो डायवर्सिटी बोर्ड के मध्य समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु शीघ्र बैठक आयोजित की जाए। देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र व फार्मासिटी होने के कारण यहां पर महिला श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक हैं। सेलाकुई फार्मासिटी में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को निर्देश दिए कि सेलाकुई चौकी को थाने में तब्दील किया जाय तथा थाने में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि दवा निर्यात बढ़ाने तथा अत्याधुनिक इकाईयों, प्रयोगशालाओं व अन्य सुविधाओं की स्थापना हेतु औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को देखते हुए अन्य ऐसे उद्योग या अस्पताल जिन्हें सरकार द्वारा पूर्व में भूमि आवंटित की गई थी परन्तु जिसका उपयोग पिछले 10 वर्ष से नहीं हुआ, ऐसे खाली पड़े भूखण्डों की सूचना एकत्र की जाए। उन्होंने कहा कि फार्मा उद्योग द्वारा अधिकाधिक संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिले इसके लिए सभी हितधारकों को मिलजुल कर काम करना होगा।

बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव श्री अमित सिंह नेगी, श्री नितेश कुमार झा, श्रीमती राधिका झा, श्रीमती सौजन्या, जिलाधिकारी श्री एस मुरुगेशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता कुकरेती, ऊर्जा निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में प्रस्तावित सौंग बांध के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को रिस्पना क्षेत्र में प्रस्तावित पौधरोपण कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता के लिए लोगों व स्कूली बच्चों को प्रेरित किया जाए। भविष्य में जो भी सीवरेज योजनाएं बनाई जाएं, उसमें सीवरेज लाईन बिछाने से पहले ट्रीटमेंट प्लांट बनाना सुनिश्चित कर लिया जाए। प्रदेश के नगर निकायों की परिधि में शामिल होने वाले नये क्षेत्रों में 10 वर्ष तक भवन कर नहीं लिया जायेगा। राजपुर रोड़ क्षेत्र में मन्नूगंज नाला को कवर किए जाने से बरसात का पानी घरों में घुस जाने की शिकायत पर अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश को इसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। इस बात का भी परीक्षण कर लिया जाए कि नालों को कवर करना कहां तक उचित है।

शनिवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा देहरादून जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यतः मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में प्रभारी मंत्री श्री यशपाल आर्य, विधायक श्री हरबंस कपूर, श्री गणेश जोशी, श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्री उमेश शर्मा काउ, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री खजानदास, श्री विनोद चमोली, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी देहरादून व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किए गए कार्यों पर पूरी गम्भीरता के साथ समयबद्ध तरीके से काम किया जाए। सभी मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी व शासन स्तर पर सचिव श्री अमित नेगी को जिम्मेवारी सौंपी।

मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित सौंग बांध के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देहरादून को पेयजल आपूर्ति में सौंग बांध बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे ग्रेविटी पर पानी की उपलब्धता रहेगी। बताया गया कि इसका फिजीबिलिटी सर्वे कर लिया गया है। जिओलॉजिकल, टेक्नीकल व हाईड्रोलॉजिकल स्टडी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने डीएम देहरादून श्री एस.एम.रुग्गेशन को 22 जुलाई को रिस्पना क्षेत्र में प्रस्तावित पौधरोपण कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। बताया गया कि इस दिन देहरादून में 2 लाख 75 हजार पौधे लगाए जाएंगे। इसमें सभी विभागों का सहयोग लिया जाएगा। स्कूली बच्चों को फलदार पौधे वितरित किए जाएंगे। जिलाधिकारी देहरादून को बिंदाल नदी से सिल्ट को हटाने के लिए भी निर्देशित किया गया।

चकराता विधानसभा क्षेत्र में सीएम घोषणाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि चकराता लाखामण्डल मोटर-मार्ग के सुधारीकरण कार्य का आंगणन एक सप्ताह में दे दिया जायेगा। पशु चिकित्सालय के लिए 45 लाख रुपये स्वीकृत हैं। 27 ग्रामों को त्यूनी से हटाकर चकराता तहसील में शामिल कर लिया गया है। चकराता-लाखामण्डल में आधुनिक शौचालय व पार्किंग सुविधा पर्यटन विभाग द्वारा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने राजकीय इण्टर कॉलेज नागथात का नाम स्वतंत्रता सेनानी श्री केदार सिंह के नाम पर जल्द से जल्द करने के निर्देश दिये। कालसी-चकराता मोटर मार्ग पर 257 मीटर के केबल ब्रिज की डी.पी.आर बनाई जा चुकी है। त्यूनी पेयजल योजना में 02 मिनी नलकूपों के लिए डीजल जेनरेटर सेटों की स्थापना व पाईपलाइनों के सुदृढीकरण का आंगणन तैयार कर लिया गया है।

विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में डांडा-जीवनगढ़-जकारिया मोटर मार्ग व एनएच 507 पर आरसीसी नाले का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। हर्बटपुर में 900 मीटर मार्ग के सुदृढीकरण का कार्य दिसम्बर तक व ढकरानी के आन्तरिक मार्गों का पुनर्निर्माण सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जमनीपुर में आन्तरिक मार्गों का पुनर्निर्माण लगभग पूर्ण कर लिया गया है। बड़वाला-जुड़डो मार्ग पर क्रैश बैरियर का 90 प्रतिशत कार्य हो चुका है। शीतला नदी पर सेतु निर्माण के लिए आंगणन भेजा गया है, जबकि गोना नदी पर सेतु निर्माण के लिए आंगणन 10 दिन के अन्दर भेजा जायेगा। कट्टा पत्थर नहर के किनारे सड़क निर्माण को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरा करने के निर्देश दिये गये।

सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में चन्द्रबनी में सम्पर्क मार्ग पर 50 प्रतिशत काम हो चुका है। गुलाटा नदी पर आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट का कार्य 15 सितम्बर से शुरू कर दिया जायेगा। मालढूंग जलाशय का फिजीबिलिटी सर्वे हो चुका है, इससे 53 गांवों को ग्रेविटी आधार पर जलापूर्ति होगी। राजावाला, कुंजाग्रान्ट व अत्कापुरी में नलकूप निर्माण, कारबारी में जलाशय निर्माण व हसनपुर पेयजल योजना का निर्माण कार्य किया जाना स्वीकृत है। भुडडी व सब्बावाला में राजकीय होमोपैथी चिकित्सालय की मरम्मत का कार्य पूरा किया जा चुका है।

धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक श्री विनोद चमोली की मांग पर ट्रांसपोर्टनगर सड़क निर्माण के प्रथम एवं द्वितीय चरण के अब तक के हुए कार्यों के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिये गये। दून विश्वविद्यालय में हिमालयन शोध संस्थान की स्थापना के लिए मुख्य सचिव को मॉनटरिंग करने के निर्देश दिये।

रायपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय रायपुर को मालदेवता मुख्य मार्ग से जोड़ने की स्वीकृति दी जा चुकी है। महाविद्यालय में चार क्लास रूम के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये गये। ननूरखेड़ा में आरसीसी मार्ग का कार्य प्रगति पर है। लाडपुर-रिंगरोड पेयजल योजना का आंगणन तैयार कर लिया गया है, एक माह में इसकी डीपीआर बना ली जायेगी।

राजपुर विधानसभा क्षेत्र में परेड ग्राउंड स्थित दून पुस्तकालय शोध केन्द्र के लिए 15 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। प्रेस क्लब भवन निर्माण के लिये 1 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत है। राजपुर रोड़ क्षेत्र में मन्नूगंज नाला को कवर किए जाने से बरसात का पानी घरों में घुस जाने की शिकायत पर अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश को इसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। इस बात का भी परीक्षण कर लिया जाए कि नालों को कवर करना कहां तक उचित है। इसके अतिरिक्त कई आंतरिक मार्गों के निर्माण एवं सुदृढीकरण की भी समीक्षा की गई है।

मसूरी विधानसभा क्षेत्र में गल्जवाड़ी पेयजल योजना व गंगोल-पण्डितवाड़ी पेयजल योजना की निविदा हो चुकी है। नया गांव, हाथीबड़कला में सामुदायिक भवन निर्माण की भी निविदा की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने मसूरी में आधुनिक शौचालयों के निर्माण जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिये। बताया गया कि मसूरी में वाहन पार्किंग के लिए चार स्थान चिन्हित किये गये हैं। भट्टा फॉल, रोवर्स केव में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। गडी कंट में ट्यूबवेल व पानी के ओवरहेड टैंक का आंगणन तैयार कर लिया गया है। नागल हटनाला में पेयजल, ट्यूबवेल की डीपीआर एक माह में तैयार कर ली जायेगी। मसूरी के लिए वैकल्पिक मार्ग

सैलाकुई-राजावाला-भाववाला-हाथीपांव मार्ग को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्राथमिकता से काम किए जाने की आवश्यकता बताई।

कैंट विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में स्वीकृत आंतरिक सड़कों के निर्माण का 70 प्रतिशत कार्य हो चुका है। बल्लीवाला चौक से अनुराग-नर्सरी तक मार्ग निर्माण व सुदृढीकरण का 30 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है। बताया गया कि कौलागढ़ में निराश्रित बालिकाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जायेगा।

ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में गुमानीवाला मार्ग, रायवाला-प्रदीपनगर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु निविदा की जा चुकी है। 20 बीघा, मीरा नगर, शिवाजी नगर, सुमन विहार में बाह्य व आंतरिक मार्गों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 07 जुलाई, 2018(सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-01(07/45)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में मासिक पत्रिका 'दृष्टि में ही सृष्टि' का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पत्रिकारिता का उद्देश्य समाज को नई दिशा देने के साथ ही जन जागरूकता का भी प्रसार करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पत्रिका अपने नाम के अनुरूप सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देने के साथ ही पत्रकारिता के आदर्शों के अनुरूप जनहित से जुड़े विषयों के समाधान की दिशा में भी आगे आयेगी।

इस अवसर पर पत्रिका के सम्पादक श्री सुभाष चन्द्र जोशी, सह सम्पादक श्री संदीप रावत सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।